(DPL) thermal power stations which were prolonged due to staff and labour trouble. This included 'work to rule' tactics adopted by engineers as well as operation and maintenance staff at the Power Stations. On 3rd June, 1971, supply from West Bengal State Electricity Board was interrupted on account of faults caused by lightning and dealy in re-commissioning of the generating units at Bande' thereafter.

Dispute between Tamil Nadu and Kerala

*658. SHRI P. NARASIMHA REDDY: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

- (a) whether the dispute between the Tamil Nadu and Kerala regarding the Siruvani waters has been settled; and
 - (b) if so, the main terms of agreement?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): (a) and (b). At an inter-State meeting held in May, 1969 the Kerala and Tamil Nadu Governments accepted in principle that a reservoir of suitable capacity should be constructed on the Siruvani by the Government of Kerala, at the cost of and in accordance with the designs and specifications of Tamil Nadu Government to enable reliable drinking water supply of 1.3 TMC to Coim batore, and that construction of the project might be proceeded with after the details were wor kedout.

The Government of Kerala have reported that they had examined the Project Report prepared by the Government of Tamil Nadu in this regard and had made certain technical suggestions, and that revised plans and estimates are recently awaited from the Government of Tamil Nadu.

A draft of the agreement to be executed between the two Governments is pending finalisation. One meeting has already been held to discuss the draft and a further meeting has to be held to discuss it further and finalise it.

मध्य प्रदेश में सुकता बांध का निर्माण

2703. श्री गंगा चरण दीक्रात: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ जिले में

सुकता बांध का निर्माण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है;

- (ख) प्रारम्भिक कार्य कब तक शुरू हो जाएगा; और
- (ग) निर्माण कार्य शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

सिंबाई और बिजुत मन्त्रालय में उपमन्त्री (भी बंजनाय कुरील): (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार ने 1968 में 6 32 करोड़ रुपये की लागत पर सुकता परियोजना का प्रस्ताव रखा था। वहरहाल, अक्तूबर, 1969 में उन्होंने सूचित किया कि एक मध्यम स्कीम बनाने के लिए वह इस स्कीम का संशोधन कर रही है। यह संशोधित स्कीम अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

मध्य प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण योजनाएं

2704. श्री गंगा चरण वीक्षितः क्या सिवाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को मेजी गई ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी योजनाओं की, जिनका वित्तपोषण ग्राम विद्युती-करण निगम द्वारा किया जाएगा, मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और
- (ख) उन पर सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

सिंबाई और विद्युत् मन्त्राख्य में उपमन्त्री (श्री बंजनाथ कुरीख): (क) और (ख). मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने ग्राम विद्युतीकरण निगम को अब तक 19 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें मेजी हैं। इनमें से पांच स्कीमें, 331.396 लाख रुपये को ऋण सहायता समेत, निगम ने स्वीकार कर दी हैं। एक स्कीम, जो व्यवहार्यता के मानदंड के अनुसार सन्तोषजनक नहीं थी, वापिस कर